संख्या-306/2025/88 के-2/22-3-2025-17(208)/2025

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,

संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 18 जुलाई, 2025

विषय:-केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुल्लू यादव पुत्र श्री सुभग्गा यादव, निवासी जनपद-आजमगढ़ की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-1910/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-09.01.2025) दिनांक-15.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुल्लू यादव पुत्र श्री सुभग्गा यादव, जो-ग्राम डीहा, थाना-जहानागंज, जनपद-आजमगढ़ का निवासी है। ग्राम प्रधानी के चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 25/26.04.2008 को बन्दी ने अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बम, कट्टा, बन्दूक व तमन्चों से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या तथा अभियुक्तगण द्वारा की गयी फायरिंग व गोलीबारी से अपने 01 अज्ञात साथी की हत्या सहित कुल 05 लोगों की हत्या की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-651/2008, में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 147, 148 व 5 वि0प0 अधिनियम के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-08, आजमगढ़ के आदेश दिनांक 15.07.2015 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक **05**.**01**.2023 तक आयु **34** वर्ष, 0**1** माह, 2**2** दिन है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुन: अपराध करने की सम्भावना से इंकार नहीं किये जाने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बंदी को जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सुल्लू यादव पुत्र श्री सुभग्गा यादव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुल्लू यादव (बन्दी संख्या-565/2022) पुत्र श्री सुभग्गा यादव, निवासी जनपद-आजमगढ़ को फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार बंदी के फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-306/2025/88 के-2/22-3-2025-17(208)/2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ

2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

3- जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़।

4- वरिष्ठ/अधीक्षक केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में दिनांक 10.09.2024 को पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-**2**, उ0प्र0 शासन।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-306/2025/88 के-2/22-3-2025-17(208)/2025

दिनांक- 18 जुलाई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुल्लू यादव पुत्र श्री सुभग्गा यादव, जो-ग्राम डीहा, थाना-जहानागंज, जनपद-आजमगढ़ का निवासी है। ग्राम प्रधानी के चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 25/26.04.2008 को बन्दी ने अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बम, कट्टा, बन्दूक व तमन्चों से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या तथा अभियुक्तगण द्वारा की गयी फायरिंग व गोलीबारी से अपने 01 अज्ञात साथी की हत्या सहित कुल 05 लोगों की हत्या की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-651/2008, में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 147, 148 व 5 वि0प0 अधिनियम के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-08, आजमगढ़ के आदेश दिनांक 15.07.2015 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक **05**.01.2023 तक आयु **34** वर्ष, 01 माह, 2**2** दिन है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुनः अपराध करने की सम्भावना से इंकार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बंदी को जेल में और आगे निरूद्व करने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सुल्लू यादव पुत्र श्री सुभग्गा यादव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।